60 वर्ग मीटर की रजिस्ट्री के स्टांप शुल्क में छूट, टीडीआर के साथ 50% एफएआर भी अतिरिक्त

निम्न मध्य आय वर्ग के लिए कम भूमि पर बन सकेंगे अधिक फ्लैट

सुविधा

शैलेंद्र श्रीवास्तव

लखनऊ। राज्य सरकार शहरों में निम्न मध्य आय वर्ग के लोगों के लिए कम भूमि पर अधिक फ्लैट बनाने की सुविधा देगी। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट (टीडीआर) के साथ 50% अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) मुफ्त दिया जाएगा। साथ ही 60 वर्ग मीटर तक फ्लैट की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क में एक फीसदी छूट मिलेगी। जल्द ही विस्तृत दिशा-निर्देश की तैयारी है।

उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में लोगों की आवासीय समस्या के समाधान के लिए सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना दो शुरू करने जा रही है। ईडब्ल्यूएस, एलआईजी मकान विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद से बनवाए जाएंगे। एमआईजी यानी निम्न मध्य आर्य वर्ग के लिए अफोर्डेबल फ्लैट बनाने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। इन बिल्डरों को कई सुविधाएं दी जाएंगी। सूडा ने शासन को विस्तृत नीति का प्रारूप भेजा है। इसके मुताबिक जून 2025 तक योजना को अमल में लाने के साथ छूट देने की बात भी कही गई है। केंद्र द्वारा तय नीति के आधार पर योजना यूपी में संचालित होगी। एक योजना में 100 घर बनेंगे। इस योजना में जो भी मकान बनेंगे, उसमें 25% मकान ईडब्ल्यूएस के होंगे। इसके साथ बिल्डरों को रेंटल आवास भी बनाने होंगे। इन मकानों को शहरी प्रवासियों, बेघर, श्रमिकोंआदि को किराए पर दिया जाएगा।

शहरों में अवैध निर्माण के लिए पुलिस भी होगी जिम्मेदार

- हाईकोर्ट के रुख के बाद नए सिरे से तय की जा रही जिम्मेदारी

लखनऊ, विशेष संवाददाता। शहरों में अवैध निर्माण रोकने के लिए विकास प्राधिकरणों के साथ स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी भी तय करने की तैयारी है। विकास प्राधिकरणों द्वारा जिस अवैध निर्माण को रोका जाएगा, वहां पुनः निर्माण शुरू होने पर इसके लिए स्थानीय पुलिस की जिम्मेवारी तय होगी। उच्च स्तर पर जल्द ही इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तैयारी है। हाईकोर्ट ने शहरों में होने वाले अवैध निर्माण पर सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने प्रदेशभर के विकास प्राधिकरणों में हुए अवैध निर्माण की रिपोर्ट मांगी थी। इसके मुताबिक पिछले 13 सालों में प्रमुख शहरों में 1.75 लाख से अधिक अवैध निर्माण हुए और 83 हजार को गिराने का आदेश हुआ। हाईकोर्ट में इस संबंध में लगातार सुनवाई चल रही है। आवास विभाग ने हाईकोर्ट में पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। हाईकोर्ट ने इस पर शासन से पूछा है कि अब तक इसके लिए जिम्मेदारी कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है।

नियोजन विभाग से निर्माण की एकीकृत रेट व्यवस्था रद्द

फैसला

लखनऊ, विशेष संवाददाता। नियोजन विभाग द्वारा प्रदेश में निर्माण के लिए जारी एकीकृत रेट व्यवस्था को रद कर दिया गया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि नियोजन विभाग द्वारा निर्माण के संबंध में जारी एकीकृत रेट व्यवस्था न तो वित्तीय हस्तपुस्तिका के अनुरूप थी और न ही यह व्यावहारिक।

सूत्र बताते हैं कि एकीकृत निर्माण दरों में इजाफा और फिर उसे वापस लेने का मामला सामने आने के बाद इस मसले पर नियोजन समेत अन्य विभागों के साथ बैठक हुई थी, जिसमें पाया गया कि नियोजन विभाग द्वारा जारी दरों को रद करना ही उचित और नियमसंगत होगा। विभागीय बैठकों के बाद उच्च स्तर पर इसे रद करने की सहमति ली गई, जिसके बाद यह फैसला हुआ है।

मुख्य सचिव ने कहा कि पुरानी व्यवस्था में अधीक्षण अभियंताओं को ही दरें तय करने का अधिकार है। अधीक्षण अभियंता भी केवल अपने प्रभार वाले जिलों के ही दरें तय कर सकते हैं। उन्हें भी साल में दो बार पुनरीक्षित किया जाना जरूरी है। वित्तीय हस्तपुस्तिका में साफ है कि दरें तय करने का अधिकार लोक निर्माण विभाग को, सिंचाई, बिजली, जल निगम और वन विभाग को अपने-अपने काम के लिए दरें तय करने का अधिकार है। ऐसे में नियोजन विभाग द्वारा जारी एकीकृत दर व्यवस्था जारी करना उचित नहीं है। अब अधीक्ष अभियंता ही पहले की तरह अपने प्रभार वाले जिलों में दरें तय करेंगे।

व्यावहारिकता की कसौटी पर भी खरी नहीं थी व्यवस्था

मुख्य सचिव ने कहा कि नियोजन विभाग द्वारा जारी एकीकृत रेट व्यवस्था व्यावहारिकता की कसौटी पर भी खरी नहीं उतर रही थी। हर निर्माण सामग्री की दरें क्षेत्रवार बदल जाती हैं। ऐसे में इन्हें एक ही जगह पर बैठककर पूरे प्रदेश के लिए लागू कर देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसके अलावा मजदूरी की दरें भी अलग-अलग जगहों पर फर्क हैं। पुरानी व्यवस्था ही वित्तीय हस्तपुस्तिका के मुताबिक नियमसंगत और व्यावहारिक है। उसे ही लागू रखा जाएगा।

सियासत 30S

प्रतिनिधिमंडल ने की रक्षा मंत्री से मुलाकात

लखनऊ। इंडियन पब्लिक सर्विस इम्प्लॉज फेडरेशन (इप्सेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र की अगुआई में रविवार को प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में उप महासचिव अतुल मिश्र, उपाध्यक्ष सुरेश रावत उपाध्यक्ष, अजय वीर यादव आदि उपस्थित रहे। प्रतिनिधिमंडल ने उनसे 25 वर्ष की जगह 20 साल पर पूरी पेंशन देने व जीपीएफ बहाल करने की मांग की। रक्षा मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को सकारात्मक आश्वासन दिया है।

सपा ने संत गाडगे की जयंती मनाई

लखनऊ। समाजवादी पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर रविवार को स्वच्छता के प्रणेता व सामाजिक समरसता के प्रतीक संत गाडगे की जयंती सादगी से मनाई गई। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी ने संत गाडगे के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल, पूर्व सांसद अरविंद कुमार सिंह मौजूद रहे।

चकबंदी विभाग के पदाधिकारियों ने शपथ ली

लखनऊ। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ चकबंदी विभाग उत्तर प्रदेश का शपथ ग्रहण समारोह संघ भवन में रविवार को संपन्न हुआ। इस मौके पर चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष हरिकेश प्रसाद सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी पदाधिकारियों में संरक्षक अनिरुद्ध प्रसाद यादव, अध्यक्ष राहुल सिंह, महामंत्री जयप्रकाश, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम श्याम, उपाध्यक्ष रवि कुमार कनौजिया, रविंद्र कुमार पुंडीर राजेंद्र कुमार शर्मा, वीरेंद्र कुमार तिवारी रहे।

टीएमएस 2.0 की शुरुआत 25 से

लखनऊ। साचीज की मुख्य कार्यपालक अधिकारी अर्चना वर्मा ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधनमंत्री जन आरोग्य योजना में ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (टीएमएस) 2.0 की शुरुआत 25 फरवरी से होगी। उन्होंने बताया कि इससे योजना को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि सूचीबद्ध अस्पतालों में से लगभग 50 प्रतिशत अस्पतालों ने यूपीएम पोर्टल पर एचईएम 2.0 और टीएमएस 2.0 के लिए आवेदन कर दिया है।

आरोग्य मेले में 1,76,632 रोगी लाभान्वित हुए

लखनऊ। मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में रविवार को 1,76,632 रोगी लाभान्वित हुए। इनमें 74,697 पुरुष, 72,585 महिला और 29,350 बच्चे शामिल थे। 1065 गंभीर रोगी पाए गए, जिन्हें उच्च चिकित्सीय संस्थानों में भेजा गया है। 3002 को गोल्ड कार्ड वितरित किए गए। मेले में 4822 चिकित्सक, 14,371 पैरामेडिकल स्टाफ, 2520 आईसीडीएफ स्टाफ ने सेवाएं दीं। यह आरोग्य मेलों का 189वां संस्करण था। अबतक मेले में 13,42,00,882 रोगी लाभान्वित हो चुके हैं।

परिवहन विभाग स्कूलों में चलाएगा अभियान

लखनऊ। परिवहन विभाग जल्दी ही ट्रैफिक नियमों के प्रति विद्यार्थियों और शिक्षकों को जागरुक करने के लिए स्कूलों में अभियान चलाएगा। यह अभियान बोर्ड परीक्षाएं खत्म होने के बाद शुरू किया जाएगा। अफसरों के मुताबिक नए सत्र शुरू होते ही यह अभियान शुरू कर दिया जाएगा। इसमें बिना हेलमेट आने पर विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रवेश न देने के बारे में सख्त करने को भी कहा जाएगा।

भाजपा समर्थकों ने सपा की सदस्यता ली

लखनऊ। समाजवादी पार्टी की नीतियों और अखिलेश यादव के नेतृत्व पर आस्था जताते हुए रविवार को कई भाजपा समर्थकों ने सदस्यता ग्रहण की। इनमें ममता त्रिपाठी, गुड़िया सिंह, राम विलास शर्मा, मोहम्मद नासिर, तारा श्रीवास्तव, पूनम जायसवाल, दलजीत कौर, अवनीश अवस्थी, अखिलेश अवस्थी, सुनीता सिंह, शिवानी, पिहू त्रिपाठी, सूरज कश्यप, पप्पू, हारून, आशा मौर्या आदि है। सभी ने उत्तर विधानसभा की पूजा शुक्ला के नेतृत्व में सदस्यता ग्रहण की।

31 मार्च तक सरकारी भवनों पर लगें स्मार्ट प्री-पेड मीटर

निर्देश

लखनऊ, विशेष संवाददाता। पावर कॉरपोरेशन चेयरमैन डॉ. आशीष गोयल ने मीटर लगाने वाली एजेंसियों को आदेश दिए हैं कि 31 मार्च तक हर हाल में सरकारी भवनों और कार्यालयों पर स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाए जाएं।

उन्होंने कहा है कि फिलहाल जिस गति से सरकारी भवनों पर मीटर लग रहे हैं, वह निराशाजनक है। अगर 31 मार्च तक सभी भवनों पर मीटर नहीं लगते हैं तो केंद्र सरकार रिवैम्प्ड डेवलपेंट सेक्टोरल स्कीम के तहत दी जाने वाली ग्रांट बंद कर देगी। अभी तक 1,15,055 सरकारी भवनों में से महज 17,440 पर ही स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगे हैं। केंद्र की स्कीम के तहत सबसे पहले सरकारी कार्यायलयों पर अनिवार्य तौर पर स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगने थे।

चेक मीटर न पर्याप्त नहीं लगे

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि सरकारी भवनों पर मीटर लगाने की रफ्तार तो सुस्त है ही, चेक मीटर भी पर्याप्त नहीं लगाए जा रहे हैं। नियमों के मुताबिक, 5% पुराने मीटर उपभोक्ताओं के घरों में ही लगे छोड़ने थे, जिन्हें चेक मीटर के तौर पर इस्तेमाल करना था।

‘एआई डेटा सेंटर से रोजगार बढ़ेंगे’

लखनऊ। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार लखनऊ में उत्तर प्रदेश का पहला एआई सिटी बना रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाकर यूपी में निवेश का नया माहौल तैयार तैयार है। एआई डेटा सेंटर की स्थापना होने के बाद प्रदेश में आईटी सेक्टर में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी।

मुख्य सचिव ने रविवार को सिफी इनफिनिट स्पेस लिमिटेड द्वारा सुल्तानपुर रोड स्थित एआई-हब डेटा सेंटर के भूमि पूजन समारोह के मौके पर यह बात कही। इसका निर्माण चार चरणों में होगा। योजना है। इस डेटा सेंटर से एनसीआर व लखनऊ से संचालित होने वाली कंपनियों को काम करने में मदद मिलेगी।

बजट में विकास को तरजीह : भूपेंद्र

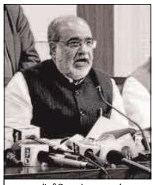

लखनऊ में मीडिया से बात करते भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी।

लखनऊ, विशेष संवाददाता। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने यूपी के बजट को रविवार को सर्वसमावेशी बताते हुए कहा कि विकास के चारों पहियों पर बजट में ध्यान दिया गया है। कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात वे चार पहिए हैं, जो अर्थव्यवस्था को आगे ले जाते हैं। ये बजट यूपी को एक ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी की तरफ ले जाने वाला है। भूपेंद्र प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया से बजट के बारे में बात कर रहे थे।

भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार का बजट भी सभी वर्गों को समाहित करके आगे ले चलने वाला है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यूपी प्रधानमंत्री के विजन को साकार कर रहा है। यूपी के बजट में अगले 25 साल का रोडमैप है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर 22%, शिक्षा पर 13%, कृषि पर 11%, चिकित्सा व स्वास्थ्य क्षेत्र में 6%, और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पर 4 फीसदी संसाधन आवंटित किए गए हैं।

भाजपा के जिला अध्यक्षों की सूची जल्द आएगी

एक सवाल के जवाब में भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा के जिला अध्यक्षों की सूची में कहीं कोई तकनीकी पेच नहीं हैं। सभी लोगों से बात की जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनावों और महाकुम्भ की वजह से प्रक्रिया में थोड़ी रुकावट आई थी। अब इस दिशा में काम आगे चल रहा है। जल्द ही सूची जारी होगी। भाजपा देश की इकलौती राजनीतिक पार्टी है, जिसमें सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा जाता है।

शून्य अपराध संख्या पर दर्ज केस दूसरे प्रदेश में स्थानान्तरित होंगे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में फरवरी 2025 में अब तक शून्य अपराध संख्या पर दर्ज 167 मुकदमों को सम्बन्धित दूसरे प्रदेशों में स्थानान्तरित ही नहीं किया गया।

इस पर डीजीपी ने नाराजगी जताई और कहा कि नए कानून के तहत शून्य अपराध संख्या पर दर्ज मुकदमों को सम्बन्धित घटनास्थल के हिसाब से दूसरे प्रदेशों में स्थानान्तरित कर दिया जाए। उन्होंने आदेश दिया है कि ऐसे मुकदमे अब डीजीपी के माध्यम से ही दूसरे प्रदेश में स्थानान्तरित किए जाएंगे।

उरई में योग कर रहे स्कूल संचालक का सिर काट डाला

वारदात

- प्रबंध समिति चुनाव का विवाद बनी मुख्य वजह
- गांव के बाहर खून से लथपथ मिला शव

रामपुरा (उरई), संवाददाता। ग्राम सिलउवा में रविवार सुबह योग कर रहे स्कूल संचालक की सिर काटकर हत्या कर दी गई। गांव के बाहर पुलिया पर खून से लथपथ सिर कटा शव मिलने से हड़कंप मच गया। शुरुआती छानबीन में वारदात के पीछे प्रबंधक का प्रबंध समिति चुनाव का विवाद पता चला है। पुलिस ने बेटे की तहरीर पर दो नामजद और चार अज्ञात पर रिपोर्ट दर्ज की है।

रामपुरा थाना क्षेत्र के सिलउवा निवासी 68 वर्षीय विद्याराम जाटव रविवार सुबह घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। गांव के बाहर प्राइमरी स्कूल के पास पुलिया पर योग करते समय पीछे से उनकी गर्दन में किसी ने धारदार हथियार से कई वार कर दिए। उनका सिर धड़ से अलग हो गया।

क्रेडिट नोट के फर्जीवाड़े में फंसे प्रदेश के कई कारोबारी

मुरादाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। जीएसटी की चोरी के मकसद से कारोबारियों की तरफ से नया पैंतरा अपनाए जाने का मामला सामने आया है। प्रदेश में कई कारोबारियों ने करापवंचन के इरादे से कथित फर्जी क्रेडिट नोट जारी किए हैं, जिसके चलते कथित तौर पर कोई कसूर नहीं होते हुए भी प्रदेश के हजारों कारोबारी कानूनी पचड़े में फंस गए हैं।

क्रेडिट नोट के फर्जीवाड़े में मुरादाबाद की पांच फर्मों के लिप्त होने का संदेह सामने आया है। मामले का खुलासा अलीगढ़ के टैक्स अधिवक्ताओं की तरफ से राज्य कर विभाग के अधिकारियों के सामने किया गया। राज्य कर अधिवक्ता संघ की कार्यकारिणी समिति की बैठक एवं जोनल टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से जीएसटी पर आयोजित प्रांतीय सेमिनार के लिए प्रदेश भर के टैक्स अधिवक्ता मुरादाबाद में जुटे, जिसमें राज्य कर विभाग के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड प्रथम, इसकी विशेष अनुसंधान शाखा के एडिशनल कमिश्नर व सीजीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर बतौर अतिथि मौजूद रहे।

हजारों कारोबारी बेवजह कानूनी शिकंजे में फंसे

राज्य कर अधिवक्ता संघ की एक्जीक्यूटिव मीटिंग के दौरान अलीगढ़ के टैक्स अधिवक्ताओं ने यह अंदेशा जताया कि प्रदेश में काफी बड़े पैमाने पर फर्जी क्रेडिट नोट जारी किए जा रहे हैं, जो कारोबारी किसी भी रूप में करापवंचन सरीखी गतिविधियों में लिप्त नहीं हैं वह अपने नाम से क्रेडिट नोट जारी होने के चलते बेवजह ही कानूनी शिकंजे की जद में आ रहे हैं।

‘कांग्रेस बहुजन मूवमेंट का अपमान कर रही’

- बसपा नेता आकाश आनंद ने उदितराज की टिप्पणी पर जताई नाराजगी

लखनऊ, विशेष संवाददाता। बसपा के राष्ट्रीय कोआर्डिनेटर ने उदितराज का नाम लिए बिना कहा है कि कांग्रेस के ये नेता बहुजन मूवमेंट का लगातार अपमान कर रहे हैं। करोड़ों दलितों, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक समाज का स्वाभिमान जगाने वाले, संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर क्या कांग्रेस की मेहरबानी की वजह से पूज्यनीय हैं?

आकाश आनंद ने रविवार को एक्स पर लिखते हुए कहा है कि पहले मायावती का गला घोंटने की धमकी देने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बाबा साहेब के योगदान पर जो अशोभनीय टिप्पणी की है, कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व के कैसे विचार है।

बदायूं: पुलिस चौकी में जहर खाकर जान दी, हंगामा

- विवाद के बाद अधेड़ को चौकी लाई थी पुलिस
- एसएसपी ने हेडकांस्टेबल को किया लाइनहाजिर

बदायूं, प्रमुख संवाददाता। बदायूं में आपसी विवाद के बाद चौकी लाए गए व्यक्ति ने शनिवार देर शाम जहरीला पदार्थ (चूहे मारने वाली दवा) खा लिया। चौकी में हालत बिगड़ने के बाद उसे जिला अस्पताल लाया गया। बाद में यहां से मेडिकल कालेज रेफर किया गया।

मेडिकल कॉलेज में हालत गंभीर बताते हुए बाहर ले जाने के लिए रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज से ले जाते समय रास्ते में ही अधेड़ की मौत हो गई। मौत के बाद शव को लेकर परिजन शनिवार देर रात आसफपुर चौकी पहुंचे और शव रखकर जमकर हंगामा किया। मामले की गंभीरता को देखते हुये एसएसपी ने हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया और जांच सीओ बिसौली को सौंपी है। फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के आसफपुर गांव के 45 वर्षीय जगतवीर सिंह यादव का अपने भाई से विवाद हो गया था। जगतवीर की पत्नी सुशीला जब शिकायत करने गई, तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट कर दी।

एनआईए ने पूर्व छात्रनेता से चार घंटे की पूछताछ

कुशीनगर। एनआईए की टीम ने पटहेरवा थाने के एक बंद कमरे में रविवार को बीएचयू के पूर्व छात्रनेता से तकरीबन चार घंटे तक पूछताछ की। टीम के सदस्यों ने उसे पुनः बुलाने पर उपस्थित होने का निर्देश दिया और चले गए। बताया जा रहा है कि फाजिलनगर कस्बा निवासी युवक बीएचयू में छात्रनेता रहा है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के संदेह में टीम ने उससे पूछताछ की है। नेट-जेआरएफ की तैयारी कर रहा है।

वैश्विक स्पर्धा के लिए खुद को तैयार करें युवा : एस.जयशंकर

- भारत में एआई का इस्तेमाल करने की अपार क्षमता
- साउथ ग्लोबल देशों के लिए भी क्रांति बन सकता है एआई
- दैनिक जीवन में भी विदेश नीति को समझने की अपील

वाराणसी, संवाददाता। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि हमारी तकनीकी प्रगति परंपराओं से प्रभावित है। विद्यार्थी अपनी सांस्कृतिक विरासत और तकनीकी प्रगति को अपनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए खुद को तैयार करें। उन्होंने कहा कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को इस्तेमाल करने की अपार क्षमता है। एआई ग्लोबल साउथ देशों (विकासशील, कम विकसित और अविकसित देश) के लिए भी क्रांति बन सकता है। यह सभी को समान अवसर देने के साथ और सतत विकास को बढ़ावा देगा। वह रविवार को बीएचयू के ओंकारनाथ ठाकुर सभागार में आईआईटी के छात्रों से संवाद कर रहे थे।

‘विश्व से संवाद-विश्व बंधु’ थीम पर आयोजित कार्यक्रम में 45 देशों के राजदूतों के साथ पहुंचे विदेश मंत्री ने पेरिस शिखर सम्मेलन में दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि भारत एआई से जुड़े सांस्कृतिक पूर्वाग्रह के मुद्दे का प्रभावी हल कर सकता है।

विदेश मंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी विकासशील देशों को पारंपरिक विकास मॉडल को छोड़कर आगे बढ़ने में सक्षम बनाती है। भारत की डिजिटल सार्वजनिक संरचना, कल्याणकारी योजनाएं और स्वास्थ्य सेवा से पता चलता है कि इसे नवाचार से जोड़ा जाए तो यह परिवर्तनकारी शक्ति बन जाता है। देश अब वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत स्थिति स्थापित कर रहा है।

कार्यालय ग्राम पंचायत मंडोरा विकास खण्ड सरधना (मेरठ)

पत्रांकः– मीमो/अन्त्येष्टि स्थल/2024–25 दिनांकः– 22–02–2025

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

ग्राम पंचायत द्वारा अन्त्येष्टि स्थल/राज्य वित्त/15 वां वित्त योजनान्तर्गत सरकारी विभागो में पंजीकृत ठेकेदारो से सीलबन्द निविदाये दिनांक 24–02–2025 से दिनांक 07–03–2025 को 02.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है निविदा प्रपत्र दिनांक 24–02–2025 से दिनांक 07–03–2025 को अपराहन 02.00 बजे तक सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्यालय से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किये जा सकते है। निविदा गठित कमेटी द्वारा इच्छुक ठेकेदारो की उपस्थिति में दिनांक 10–03–2025 को 12.00 बजे खोली जायेगी। नियमानुसार धरोहर राशि एन०एस०सी०/एफ०डी०आर० के रुप में जमा करानी होगी। जो ग्राम पंचायत मंडोरा के नाम से बंधक होगी।

क्रम सं०	योजना का नाम	स्वीकृति कार्य का विवरण	कार्य की माप	स्वीकृति लागत अनुमानित	निविदा मूल्य+ 18% GST	धरोहर राशि	कार्य की अवधि
1	अन्त्येष्टि स्थल/ राज्य वित्त/15 वां वित्त	ग्राम मंडोरा में अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण	01	24.36 लाख रु०	500+GST	2%	6 माह

नियम व शर्ते :– 1. निर्माण सामग्री/कार्य लो० नि० वि० एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप होने चाहिये। 2.सम्बन्धित फर्म अथवा ठेकेदार का लोक निर्माण विभाग अथवा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग अथवा जिला पंचायत जैसी संस्था में पंजीकृत होना अनिवार्य है। 3. इच्छुक पंजीकृत ठेकेदार 07–03–2025 तक किसी भी कार्य दिवस में 2 बजे तक निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते है। प्राप्त निविदाओ की समीक्षा उपरान्त सबसे कम दरो वाली निविदा की स्वीकृति प्रदान की जायेगी। 4. निविदाओ को निरस्त करने का अधिकार पूर्ण रुप से गठित कमेटी में निहित होगा। 5. न्यूनतम निविदा के स्वीकृत होने की स्थिति में फर्म/ठेकेदार के बिल से 8 प्रतिशत धनराशि जमानत राशि टी०डी०एस० जी०एस०टी०, लेबरसेस नियमानुसार काटा जायेगा। जिसे सम्बन्धित हैड में जमा कराया जायेगा। निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण कराना आवश्यक होगा। निर्माण कार्य की मात्रा कार्यस्थल की आवश्यकता अनुसार घट–बढ़ सकती है। सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा नियमानुसार रायल्टी जमा करनी होगी। 6. निर्माण सामग्री की गुणवत्ता व कार्यस्थल पर हुयी किसी भी प्रकार की कमी/त्रुटि की पूर्ण जिम्मेदारी फर्म अथवा ठेकेदार की होगी। 7. टेंडर खुलने के दिनांक को अपरिहार्य स्थिति में अवकाश घोषित होने पर अगले कार्यदिवस में टेंडर खोले जायेगे।

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत मंडोरा
वि०ख० सरधना (मेरठ)

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत मंडोरा
वि०ख० सरधना (मेरठ)

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना : अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु अल्पकालीन ई–निविदा दो भागों (प्रथम एवं द्वितीय) में ऑनलाइन आमंत्रित की जाती है। अधोलिखित आमन्त्रित अल्पकालीन ई–निविदा में प्रतिभाग करने की अन्तिम तिथि 11.03.2025 एवं समय 17:00 बजे होगी एवं निविदा के प्रथम भाग खोलने की तिथि 12.03.2025 एवं समय 12:00 बजे निर्धारित है। (1) निविदा विशिष्टीकरण संख्याः–41/वि०जा०वि०मं०/मेरठ/2024–25: विद्युत परिवर्तक मरम्मत कार्यशाला बड़ौत जनपद बागपत में स्टोर रूम, अवर अभियन्ता कक्ष एवं अन्य विविध जानपदीय निर्माण कार्य। निविदा शुल्क रू0 3,540.00 (जी०एस०टी० सहित) धरोहर धनराशि रू0 21,500.00 । (2) निविदा विशिष्टीकरण संख्याः–42/वि०जा०वि०मं०/मेरठ/2024–25: विद्युत परिवर्तक मरम्मत कार्यशाला थाना भवन, जिला शामली पर स्टोर रूम एवं कार्यालय भवन का निर्माण कार्य एवं टीन शेड की छतों की मरम्मत का कार्य। निविदा शुल्क रू0 3540.00 (जी०एस०टी० सहित) धरोहर धनराशि रू0 19,500.00 । कृपया विस्तृत जानकारी, डाउनलोड, अन्य संशोधन, निविदा प्रस्तुत करने की तिथि एवं विस्तारीकरण/शुद्धिकरण आदि सम्बन्धी सूचनाओं हेतु www.pvvnl.org एंव E-Tendering website www.etender.up.nic.in पर लॉग ऑन करें। राष्ट्र हित में बिजली बचायें, अधीक्षण अभियन्ता (जानपद) मेरठ। बिजली चोरी की सूचना हेल्पलाईन नम्बर पर दें : 1800–180–3002 (मेरठ), 1800–180–8752 (लखनऊ)। पत्रांकः 1487, दिनांकः 22.02.2025

कार्यालय नगर पंचायत हर्रा (मेरठ)

पत्रांकः– 536 / न०पं०ह० / 2024–25 दिनांक– 22/02/25

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

नगर पंचायत हर्रा जनपद मेरठ में अन्त्येष्टि स्थल विकास योजना / नगरीय झील / तालाब / पोखर संरक्षण योजना / पेयजल हेतु व्यवस्था योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से कराये जाने वाले निर्माण कार्य की निविदा ई–निविदा प्रणाली के अन्तर्गत अनुभवी ठेकेदारों / फर्मों से उनकी वित्तीय बिड आधारित निविदाएं दिनांक 17.03.2025 को दोपहर 12:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 17.03.2025 को दोपहर 02:00 बजे खोली जायेगी। निविदा का विस्तृत विवरण टेण्डर प्रपत्र शर्तें आदि उत्तर प्रदेश की ई– प्रिक्योमेन्ट की वेबसाइट www.etender.up.nic.in से प्राप्त किये जा सकते है। ई–निविदा की समस्त कार्यवाही उक्त वेबसाईट के माध्यम से ही पूर्ण की जायेगी, निविदा की सूचना / शर्तें किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

ई–निविदा समय सारणी (www.etender.up.nic.in पर)

Tender Reference	
Publish date and Time for RFP.	24/02/2025 at 04:00 PM
Last Date time for Submission of Tender	17/03/2025 till 12:00 PM
Date and time for Opening of E-Tender	17/03/2025 at 02:00 PM

(नीति गुप्ता)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत हर्रा, (मेरठ)

(कुंवर मौ० अली)
अध्यक्ष
नगर पंचायत हर्रा, (मेरठ)

सी.एस.आई.आर.-हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान
पालमपुर (हिमाचल प्रदेश)
विज्ञापन संख्या- 15/2024

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि : 24.02.2025 (10.00 प्रातः)
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि : 24.03.2025 (11.30 अप्रा.)
ऑनलाइन जनरेट किए गए आवेदन की हार्ड कॉपी प्राप्त होने की अंतिम तिथि : 04.04.2025 (05.30 अप्रा.)

(दूर-दराज के क्षेत्रों, जैसे- उत्तर पूर्वी क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला, केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख आदि में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए, ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 09.04.2025 है) (शाम 05.30 बजे)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अनुसंधान/एसएंडटी प्रबंधन करियर के लिए एक अनूठा अवसर

उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकॉर्ड और अपेक्षित अनुभव सहित प्रमाणित वैज्ञानिक उपलब्धियों तथा उच्च स्तर की प्रेरणा वाले उत्साही युवा भारतीय शोधकर्ताओं से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वैज्ञानिक के निम्नलिखित पदों की रिक्तियों को भरने के लिए अनुसंधान/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन को एक कैरियर के रूप में अपनाने की इच्छा रखते हों।

क्रमांक	पोस्ट कोड संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या एवं श्रेणी	क्षेत्र	**ऊपरी आयु सीमा (विज्ञापन में उल्लिखित ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को) निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए
7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स लेवल 11, रु. 1,20,000/- लगभग। (मूल वेतन, डीए, एचआरए, टीए आदि शामिल)					
1.	एससीटी - 15001	वैज्ञानिक	01. पीडब्ल्यूबीडी/(ओएच) PwBD(OH)	पादप जैव रसायन	32** वर्ष
2.	एससीटी - 15002		01. ईडब्ल्यूएस / EWS	कीटाणु - विज्ञान	
3.	एससीटी - 15003		01. अनारक्षित / UR	प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शन	
4.	एससीटी - 15004		01. ओबीसी (एनसीएल)/OBC(NCL)	व्यापार विकास	
5.	एससीटी - 15005		01. ओबीसी (एनसीएल)/OBC(NCL)	कृषि इंजीनियरिंग	
6.	एससीटी - 15006		01. अनारक्षित / UR	जैव प्रसंस्करण	
7.	एससीटी - 15007		01. अनुसूचित जाति / SC	जीआईएस और रिमोट सेंसिंग	
8.	एससीटी - 15008		01. अनारक्षित / UR	ज्ञान प्रबंधन	
9.	एससीटी - 15009		01. पीडब्ल्यूबीडी (एचएच/ओएच) PwBD (HH/OH)	कवक/मशरूम	
10.	एससीटी - 15010		01. ईडब्ल्यूएस / EWS	सामग्री रसायन शास्त्र	
11.	एससीटी - 15011		01. ओबीसी (एनसीएल) OBC (NCL)	फसल सुरक्षा (प्लांट पैथोलॉजी)	

योग्यता, आयु में छूट, चयन का तरीका, आवेदन कैसे करें, अपडेट यदि कोई हो आदि के संबंध में विवरण के लिए कृपया इस संस्थान की वेबसाइट i.e. https://www.ihbt.res.in पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन संख्या 15/2024 देखें।

हस्ता/-
प्रशासन नियंत्रक